



# संपादकीय

## मतदाताओं का ध्यान

यह प्रदाशित करने के लिए मजबूर किया गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम वास्तव में व्यावहारिक हैं, नरेंद्र मोदी शासन में कनिष्ठ मंत्री, मतुआ समुदाय के शांतनु ठाकुर ने नए नियमों के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने का अपना इरादा घोषित किया है। उनकी तीव्र घोषणा यह साबित करती है कि नए नियमों के तहत नागरिकता आवेदनों के सबसे मजबूत पैरोकार भी समझते हैं कि प्रक्रिया में खामियाँ हैं। केंद्र सरकार में एक मंत्री के रूप में, ठाकुर को नागरिक बनने के लिए आवेदन क्यों करना पड़ता है, यह एक सवाल है जो पश्चिम बंगाल में हंसी का पात्र है। उनके इस कदम से राज्य में मटुआ समुदाय के हजारों सदस्यों के लिए समस्या का पता चलता है, जो अपनी स्थिति की पुष्टि करने वाले नागरिकता आवेदन के बिना भी सरकारी सेवकों, रक्षा कर्मियों और अर्धसैनिक सेवाओं में कार्यरत हैं। जो लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं और भारत में रह रहे हैं वे नागरिक हैं, जैसे ठाकुर हैं। ममता बनर्जी के लिए, ठाकुर का कबूलनामा उस उपहार के लिए एक बोनस है जो मोदी शासन ने सीएए नियमों को अधिसूचित करके उन्हें दिया था। यह घोषित करने के बाद कि 1971 में बांग्लादेश से आए लोग समान अधिकार वाले नागरिक थे और पश्चिम बंगाल में कोई हिरासत शिविर नहीं होंगे, सीएए पर मटुआ समुदाय के भीतर भ्रम की स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि बनर्जी हमेशा से सही रही हैं और मोदी शासन सही था। सीमा पार से आकर बसने वालों की पहचान के बारे में संदेह पैदा करके आबादी को विभाजित करने का इरादा है। नागरिकता का हौवा खड़ा करके बांग्लादेश सीमा पर हिंदू बोटों को हड्डपने की भाजपा की उम्मीदों से अधिसूचना से मिलने वाला लाभ नहीं मिल पाएगा। सांप्रदायिक धर्वीकरण की आग को भड़काने में अपनी विफलता के कारण अवसर की हानि कम से कम आधा दर्जन लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करेगी जहां पार्टी सीएए ब्लास्टरस्ट्रोक्ष

के दशक में उन्हें जनता का प्रतिनिधि माना जाने लगा। उनके समर्थकय और अब लोग सोचते हैं कि वे अपने दलालों को चुनते हैं।” कृष्णांधी ने 1985 में इसी शब्द का उपयोग करते हुए दोहराया था जब उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की सत्ता—दलाल के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति की निंदा की थी। हालाँकि, न तो कृष्णांधी और न ही राजीव गांधी ने राजनेताओं की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए कुछ भी किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रदर्शन की बदौलत राजनेताओं के प्रति लोकप्रिय सम्मान काफी हद तक बहाल हो गया है। वधानमंत्री द्वारा स्थापित चीजों को कार्यान्वित किया जा सकता है। इससे आम तौर पर राजनीतिक वर्ग के प्रति समग्र तिरस्कार में काफी कमी आई है। राजनीति और राजनेताओं के प्रति ऐसी अवमानना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अब जबकि जमीनी हालात काफी हद तक बदल गए हैं, तो क्या हम चुनावी अभियानों की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद कर सकते हैं? चूंकि चुनाव आयोग ने चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है,

A political cartoon by SCA. It depicts a massive wooden wheel, possibly a watermill or a large gear, with the letters 'SCA' and 'SOCIAL MEDIA' written on its side. A hand is shown pulling a lever or chain attached to the wheel, causing it to turn. Underneath the wheel, a small, thin figure of a person is being crushed or flattened, symbolizing the power and control exerted by social media platforms like Facebook over individuals.



को प्रतिबिवित किया जाना चाहिए। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के विवेकपूर्ण उपयोग का विवरण इसमें अवश्य होना चाहिए। इसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि प्रतिनिधि किस हद तक यह सुनिश्चित करने में सक्षम है कि अधिकतम संख्या में पात्र व्यक्तियों ने सरकारी कल्याण कार्यक्रमों और विकास योजनाओं का लाभ उठाया है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि को दिए गए आश्वासनों और उन पर कार्रवाई के बारे में एक बयान दर्ज करने के लिए भी बाध्य किया जाना चाहिए। संबंधित स्तरों पर चुनाव लड़ रहे दलों द्वारा घोषणापत्रों का अनिवार्य प्रकाशन, उसके बाद की गई कार्रवाई की अनिवार्य रिपोर्ट बहुत मददगार साबित होगी। यहां तक कि चुनाव हारने वाली पार्टियों से भी अपने वादों को पूरा करने के प्रयासों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा जा सकता है। यदि ऐसे उपाय लागू किए जाते हैं, तो वे स्वचालित रूप से एक प्रतिनिधि की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेंगे, जिससे सूचित मतदान की सुविधा होगी। ये जवाबदेही उपाय रेवड़ी वितरण के माध्यम से लोकप्रिय समर्थन हासिल करने के प्रयासों को रोक देंगे। जितना

# पाक से क्यों खफा

# है इस्लामिक मुल्क

आर.के

پاکیستان مें آजकल سिफरूनी हालात ही खराब नहीं हैं, उनके सामने कई गंभीर संकट और हैं। उसे उसके दो पड़ोसी देशों ने उसकी तरह से ही इस्लामिक धरात हैं, उससे सख्त नाराज हैं। लेकिन और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान आमने-सामने हैं। उनमें मुल्कों के बीच सरहद पर झड़प भी हुई है। झड़प की शुरूआत केस्तान की तरफ से विगत मध्यावर को हुई थी। इसके जवाब अफगान तालिबान ने भी सीमा पाकिस्तानी चौकियों पर लीबारी की। ऐसे में सवाल है क्या दोनों देश युद्ध की ओर चल रहे हैं? पाकिस्तान के हमलों के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को नावनी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता पर किसी तरह के उल्लंघन के गंभीर अणाम होंगे। इसके साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान की नवगठित सेक्यूरिटी कार से दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को खतरे में डालने के लिए गैर-जिम्मेदाराना कार्यों की व्युत्पत्ति नहीं देने का भी आग्रह किया। दरअसल पाकिस्तान में हाल

के आतंकवादी हमलों को लेकर दोनों देशों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। पाकिस्तान का आरोप है कि हमले अफगानिस्तान की सरजर्मी से किए गए थे। जबकि, पाकिस्तान ने पाकिस्तान के इस दावे को गलत बताया है। आपको याद होगा कि बीते जनवरी के महीने में पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकानों पर ईरान ने हमला बोला था। ईरान ने पिछली 16 जनवरी को पाकिस्तान में आतंकवादी समूह जैश अल-अदल के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए थे। ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से कहा गया था कि हमले में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ईरान ने पाकिस्तान में बलूची आतंकी समूह जैश-अल-अदल के दो ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया था। ईरान ने आठ साल पहले सन 2016 में भी पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर मोर्टार दागे थे। इसलिए कहा जा सकता है कि ईरान पहले भी पाकिस्तान को निशाना बना चुका है। पाकिस्तान और ईरान के बीच 900 किलोमीटर की सीमा है। उद्धर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच करीब 2400 किमी० लम्बी अन्तराष्ट्रीय सीमा है। इसका नाम

दूरुण्ड रेखा है। दरअसल पाकिस्तान मौर और अफगानिस्तान के संबंध तब लगातार खराब होने लगे जब पाकिस्तान ने पिछले साल अपने देश से अवैध अफगानों को निकालने लगा सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तान से रोज़ सैकड़ों अफगान अपने देश वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर जारी अफगानिस्तानियों का कहना है कि वे गुजरे कई दशकों से पाकिस्तान में हैं। वे पाकिस्तान के आगरिकता भी ग्रहण कर चुके हैं। उसके बावजूद उन्हें लगातार लाताड़ित किया जा रहा है। यहां पर बड़ा सवाल यही है अपने को इस्लामिक संसार का नेता कहने वाले पाकिस्तान से इस्लामिक मुल्क में खफा क्यों है? इस सवाल का अधीधा सा उत्तर है कि पाकिस्तान ने डीएनए में ही अपने पढ़ोसियों के लिए संकट पैदा करना है। उसने भारत के खिलाफ क्या—क्या हथकंडे भी अपनाए। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 1948, 1965, 1971 में बुद्ध छेड़े और बुरी तरह से मार भी बाई। जंग के मैदान में धूल में मिलने के बाद पाकिस्तान ने 1999 में करगिल में घुसपैठ की। तब भी उसका बहुत बुरा हश्श हुआ। पाकिस्तान के साथ दिवकत यही

कि वह बुरी तरह पिटने के बाद सबक नहीं लेता। उसे बार-बार पिटने की आदत सी हो गई है। कलहाल वह ईरान और अफगानिस्तान से पिटने के लिये यार है। अब पाकिस्तान के बांगलादेश से संबंधों की भी जरात कर लीजिए। 1971 तक बांगलादेश हिस्सा था, पाकिस्तान था। अब दोनों जानी दुश्मन हैं। दोनों एक-दूसरे को फूटी नजर भी हींदे देख पाते। क्यों? बांगलादेश ने 1971 के नरसंहार के गुनाहगार और जमात-ए-इस्लामी के नेता गासिम अली को फांसी पर छाटकाया तो पाकिस्तान को एकलीफ होने लगी। बांगलादेश ने आप शब्दों में कह दिया कि वह पाकिस्तान की ओर से उसके आतंकिक मसलों में हस्तक्षेप बर्दाशत हीं करेगा। दोनों मुल्कों के संबंधों तत्वीयी को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को खंगाल लेना ही रहेगा। शेरे-ए-बंगाल कहे गए वाले मुस्लिम लीग के मशहूर तत्त्वात्. के फजल-उर-हक ने ही 3 मार्च, 1940 को लाहौर के मिन्टो पार्क (अब जिन्ना पार्क) में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। इस तारीखी सम्मेलन में संयुक्त

बंगाल के नुमाइँदों की बड़ी भागेदारी थी। वे सब भारत के मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कर रहे थे। सात साल के बाद 1947 में पाकिस्तान बना और फिर करीब 25 बरसों के बाद खंड-खंड हो गया। ईरट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में दुनिया के मानचित्र पर सामने आता है। यानी पाकिस्तान से एक और मुल्क निकला। और, जो दोनों मुल्क कभी एक ही मुल्क के हिस्सा थे, अब एक-दूसरे की जान के प्यासे हो गए हैं। 1971 में जिस नृशंसता से पाकिस्तानी फौजों ने ईरट पाकिस्तान के लाखों लोगों का कत्लेआम किया था, उसको लेकर ही दोनों मुल्क लगातार आमने-सामने रहते हैं। मैं स्वयं इस नरसंहार का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं उस समय युद्ध संवाददाता के रूप में लगभग डेढ़ वर्ष भारतीय सेना के साथ बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में रहा था। बांग्लादेश में उस कत्लेआम के गुनाहगारों को लगातार साक्ष के आधार पर न्यायालय से दंड मिलता रहा है। यह बात पाकिस्तान को गले नहीं उत्तरती। पाकिस्तानी सीरियलों और नाटकों में बांग्लादेशियों को बेहद हिकारत से दिखाया जाता है। उन्हें दोषम दर्ज का इंसान बताया जाता है। अब समझ लें कि पाकिस्तान समाज कितनी बेशर्मी से बांग्लादेशी मुसलमानों का मजाक बनाता है। वैसे पाकिस्तान अपने को सारी दुनिया के मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होने का दावा करता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भी पाकिस्तान से शिकायत रही है कि वह हर उस मौके पर बांग्लादेश सरकार को कोसता है जब वहां पर 1971 के मुक्ति संग्राम के गुनाहगारों को फांसी दी जाती है।

यानी पाकिस्तान से सब नाखुश और नाराज हैं। इस बीच, पाकिस्तान में तो आजकल हाहाकार मच दुआ है। महंगाई के कारण आम पाकिस्तानी दाने-दाने को मोहताज है। रमजान के महीने में लोग भारी कष्ट उठा रहे हैं। बेरोजगारी, अराजकता, कठमुल्लों और मोटी तोंद वाले सेना के अफसरों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। ये स्थिति दुखद और दुर्भार्यपूर्ण है। पर इस स्थिति के लिए पाकिस्तान खुद ही जिम्मेदार है। उसने शिक्षा की बजाय सेना के बजट को बढ़ाया है। इसलिए वह लगातार गर्त में जा रहा है। उससे इस्लामिक देश भी संबंध बनाकर रखने को तैयार नहीं हैं।

# **कर्नाटक बीजेपी खेमे में असंतोष, कांग्रेस में उदासीनता**

## लालत

परनाटक न पाग्रेस जार बाजिपा  
नों ही मुश्किल हालात में दिख  
ते हैं। जहां कांग्रेस कई निर्वाचन  
में उम्मीदवारों को खोजने के  
ए संघर्ष कर रही है, वहीं राज्य  
28 लोकसभा सीटों में से 20 पर  
उम्मीदवारों की घोषणा के बाद भाजपा  
कुछ सीटों पर विद्रोह का सामना  
ना पड़ रहा है। दोनों पार्टियों के

कम करके नहा आका जा सकता। भाजपा यहां अच्छा प्रदर्शन कर रही है इसने 2019 में 25 सीटें जीतीं और एक निर्वलीय, फिल्म स्टार और वर्ष केंद्रीय मंत्री अंबरीश की पत्नी मुमालता को जीत दिलाने में मदद की। लोकसभा में 370 सीटों के अपने सपने को साकार करने के लिए पार्टी के लिए दक्षिण भारत में प्रवेश द्वारा महत्वपूर्ण है, जबकि यहां से उत्तरी भूमि से आए विधायकों के बीच विभिन्न

आम चुनाव में हुई बदनामी से गहर निकलने के लिए महत्वपूर्ण है। करीब एक साल पहले विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने इस बार 20 सीटों का लक्ष्य रखा है। आजपा जद (एस) के साथ गठबंधन है, जिसने 2019 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। पिछले हफ्तों में, कांग्रेस ने सिद्धारमैया सरकार के लगभग 10 मंत्रियों को नियमित रूप से दिया गया है।

धघ लाकन सभा न  
नकार कर दिया। कुछ अन्य विध  
यकों को मनाने की कोशिशें चल  
ही हैं, लेकिन वे भी अनिच्छुक नजर  
रहे हैं। इसने उन सात सीटों पर  
मीदवारों की घोषणा की है जहां  
मीदवारों को लेकर कोई समस्या  
ही थी। उमीदवारों को खोजने का  
पर्व बैंगलुरु शहर की तीन सीटों  
र अधिक स्पष्ट है, जिन पर पार्टी  
से आप से भी उर्फ़ पार्टी है। उ

# ग्रेस में उदासीनता

1991 से बगलुरु दाक्षण्य साट हार रही है। भगवा दल ने नौ मौजूदा सांसदों को हटा दिया (उनमें से कुछ सेवानिवृत्त होना चाहते थे), 10 सांसदों को पार्टी कैडर के विरोध का सामना करने के बावजूद फिर से नामांकित किया, और प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन डॉ. सीएन मंजूनाथ (बिंगलोर ग्रामीण) सहित सात नए चेहरे लाए। पूर्व पीएम एच डी देवेगोड़ा के दामाद, अप्पा रामेश्वरी विश्वासनाथ त्रैपाल तुमकुर, बादर, विजयपुरा, काप्पल, हावेरी, दावणगेरे, चामराजनगर, बैंगलुरु उत्तर, चिकबल्लापुर, चिरदुर्ग, हासन और उत्तर कन्नड़ में अलग-अलग कारणों से पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री और राज्य में भाजपा के संस्थापक सदस्य केएस ईश्वरप्पा ने अपने बेटे केर्ने कंथेश को हावेरी से टिकट नहीं देने पर आर्प्ति से उत्तराधिकारी बन गई।

# सोशल मीडिया

21

विनाद  
समकालीन समाज ने सोशल मीडिया का बोलबाला देखा है, जो उन सभी लोगों का मुख्यपत्र है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। एक ओर, मुक्त भाषण ने सोशल मीडिया पर हानिकारक सामग्री और दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप साइबरनेटिक संघर्ष हुए हैं – जो आभासी बातचीत से परे लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। दूसरी ओर, उसी सोशल मीडिया ने शांति के प्रचार-प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया है। सोशल मीडिया ने समाज के हर वर्ग के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों को प्रस्तुत किया है – जो संघर्ष दस्तों और शांतिदूदों दोनों के लिए समान रूप से सुलभ है, अर्थात्, संपूर्ण समुदाय शांति और युद्ध दोनों को दर्शाता है। रूस-यूक्रेन युद्ध यह समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि सरकारों द्वारा सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध कोई सार्थक समाधान लाते हैं या नहीं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से सोशल मीडिया ने निर्णयक भूमिका निभाई है। सोशल नेटवर्किंग साइटें लड़ाई और बम विस्फोटों के वीडियो, मीस्स और संघर्ष के बारे में संदेशों के अलावा युद्ध पीड़ितों और शरणार्थियों के वसीयतनामा से भर गई हैं। संघर्ष ने संगठित प्रचार अभियानों को भी जन्म दिया है जो दुनिया भर में तेजी से फैल गए, मुख्य रूप से सोशल मीडिया नकली कठपुतलियों के माध्यम से – चर्चाओं या विचारों में हेरफेर करने के लिए नकली ऑनलाइन पहचान। पूरी स्थिति ने

रखी है कि सोशल मीडिया सँकेतपुतलियाँ सूचना युद्ध में कैसे मूमिका निभाती हैं। बहरहाल, रूस—यूक्रेन संघर्ष में, सूचना युद्ध पारंपरिक प्रचार तक सीमित नहीं रहा है। इसमें डिप्लेटफॉर्म्सइजेशन को शामिल किया गया है, जिसका अर्थ है सोशल मीडिया नेटवर्क सहित डेलीवरी चौनलों तक पहुंच से इनकार करना। शांति के लिए उपकरण इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, जब इसे शांति का एक साधन माना जाता है। हालाँकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि सोशल मीडिया पहले से ही विभिन्न अन्य सेत्रों में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में स्थापित हो चुका है। इस उपकार, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं

के माध्यम से शांति स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया अनुप्रयोगों ना विस्तार, प्रभावशाली संवाद और अध्यस्थता प्रक्रियाओं को स्थापित करेगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मीडिया परिदृश्य मौलिक रूप से बदल रहा है और अधिक से अधिक लोग वेब चैनलों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो आख्यधारा मीडिया के लिए एक बड़ी युनौती है। आखिरिकार, साइबररेप्येस के अपने नियम और मानदंड हैं। हर वर में मौजूद शक्तिशाली स्मार्टफोन और उनके सोशल मीडिया प्लिकेशन ने हर किसी को बैनलाइन सामग्री का उपभोक्ता बना दिया है। सर्वव्यापकता और नन्तरक्रियाशीलता सोशल मीडिया की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो साभारी प्रभावशाली लोगों को

जो बनाती हैं जो सहकर्मी नेताओं  
भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया  
माध्यम से शांति को बढ़ावा देने  
लिए, संघर्ष के आभासी माहौल  
समझना महत्वपूर्ण है और यह  
योगों को जैसे प्रभावित करता है।  
सके अलावा, व्हाट्सएप, फेसबुक  
और एक्स जैसे प्लेटफार्मों की जांच  
उनकी आवश्यकता है, क्योंकि ये  
नेटफॉर्म सार्वजनिक कूटनीति के  
हत्यारे उपकरण बन गए हैं, जिससे  
प्रतिदूतों के लिए इन अनुप्रयोगों का  
प्रयोग करना चुनौतीपूर्ण हो गया  
। निस्संदेह, सोशल मीडिया बहस,  
आमाजिक आंदोलनों और राजनीतिक  
विर्वतन को आगे बढ़ाने में एक  
हत्यारे प्रेरक शक्ति बन गया है।  
लाँकि, दूसरे छोर से, उनका  
प्रयोग हिंसा भड़काने, समाज को  
भाजित करने और सशस्त्र समूहों  
— जो भी हैं — को देखने में

The illustration depicts a group of diverse individuals represented by their hands, reaching upwards towards a clear blue sky. Each hand is holding a piece of white, crumpled paper, symbolizing discarded documents or ideas. One hand prominently holds a yellow megaphone, suggesting amplification or communication. The overall theme is one of collective action, protest, or the sharing of important messages.



